

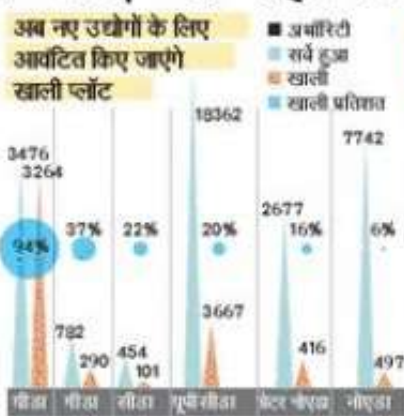
औद्योगिक विकास विभाग ने 33,493 औद्योगिक प्लॉटों का किया सर्वे, 8235 मिले खाली, सबसे ज्यादा यीडा के प्लॉट मिलने के वर्षों बाद भी नहीं लगाई इंडस्ट्री, अब निरस्त होंगे

Anand, Tripathi
@timesofindia.com

लखनऊ : प्रदेश में निवेशकों को आसानी से जमीन मिल सके, इसलिए औद्योगिक विकास विभाग ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉटों को खिड़िल करना शुरू कर दिया है जिन पर अलॉटमेंट के कई साल बाद भी कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकी है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग प्लॉटों का सर्वे करा रहा है। अब तक सबसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के 77 प्रतिशत प्लॉटों का सर्वे पूरा हो गया है। 33,493 प्लॉटों के सर्वे में करीब 25 प्रतिशत प्लॉट खाली पड़े मिले हैं।

यहाँ, 15 प्रतिशत प्लॉट गैर कार्याशील हैं। अब औद्योगिक विकास विभाग ऐसे प्लॉटों के आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से खाली प्लॉटों का आवंटन करने की तैयारी कर रहा है।

कई प्लॉटों पर इंडस्ट्री लगी पर चल नहीं रही
सर्वे एजेंसी की ओर से कराया गया 33,493 प्लॉटों के सर्वे में 8235 प्लॉट खाली पाए गए हैं। यहाँ, 5123 प्लॉट अन्य गैर कार्याशील श्रेणी (जहाँ इंडस्ट्री लगी तो संकेतित चल नहीं रही) में मिले हैं। 17,095 प्लॉटों में खनिजिक संकलन शुरू हो गया है। यहाँ, 3040 प्लॉटों में इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है।



यूनीसीड और यीडा में खाली प्लॉटों की संख्या ज्यादा

सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि यीडा में सबसे ज्यादा प्लॉट खाली हैं। यीडा में करीब 3264 प्लॉट खाली हैं। 6 अन्य गैर कार्याशील हैं। यीडा में कुल 3476 प्लॉटों का सर्वे किया जा चुका है। यहाँ, यूनीसीड के 18362 प्लॉटों का सर्वे किया गया, जिसमें से 3465 अन्य गैर कार्याशील श्रेणी में पाए गए हैं, जबकि 3667 प्लॉट बिक पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 7742 औद्योगिक प्लॉटों का सर्वे किया गया, जिसमें 1135 अन्य गैर कार्याशील श्रेणी में और 497 प्लॉट खाली पाए गए हैं। डेहरादून में 2677 प्लॉटों के सर्वे में 416 प्लॉट बिक पाए गए हैं।

क्यों करवाया जा रहा सर्वे?

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल सॉल्यूट का आयोग किया था। जिसमें राज्य सरकार को 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इन निवेश

प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए इंडस्ट्री को औद्योगिक भूखंड मुहैया करवाने में दिक्कत आ रही है। बार-बार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में कई आवंटित प्लॉट खाली हैं।

इन्हीं शिकायतों के आधार पर इंडस्ट्री विभाग सर्वे करा रहा है, जिससे खाली पड़े प्लॉटों का आवंटन निरस्त कर नए उद्योगों को जमीन मुहैया कराई जा सके। इससे प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके।

Next Lens
खबरों के अंदर की बात